प्रीलिम्स फैक्ट्स : 22 जून, 2018

राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018
(NATIONAL YOGA OLYMPIAD-2018)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा नई दिल्ली में 18 से 20 जून के बीच तीन दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2018 का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन यूनेस्को में निदेशक तथा इसके दिल्ली में स्थित कार्यालय में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा मालदीव के लिये प्रतिनिधि एरिक फाल्ट द्वारा किया गया।

उद्देश्य

- योग ओलंपियाड का उद्देश्य बच्चों में योग के प्रति जागरूकता, टीम भावना तथा आत्मविश्वास पैदा करना है।

नोडल निकाय

- एनसीईआरटी लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कर रही है। इसमें 26 राज्यों और चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के 500 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। पिछले वर्ष इसमें 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था।

प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ समय से ओलंपियाड के माध्यम से वैज्ञानिक और समग्र जीवन शैली के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। इसका उद्देश्य लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और समाज में शांतिप्रिय जीवन पद्धति को बढ़ावा देना है।
- योग की सीमा महिला-पुरुष, संस्कृति एवं भाषा से आगे है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह उम्र एवं सक्षमता से भी आगे पहुँचती है तथा सामाजिक रूप से कहा जाए तो यह सभी के लिये समान रूप से लाभकारी है।

7-स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना
(7-Star Gram Panchayat Indrahanush Yojna)

हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल के तहत 7-स्टार ग्राम पंचायत इन्द्रधनुष योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पंचायतों को सात सामाजिक मानदंडों के आधार पर स्टार रैंकिंग प्रदान की जाती है।

- इस योजना के तहत राज्य के करीब 1,120 गाँवों को स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है, स्टार रेटिंग प्राप्त इन गाँवों को 'स्टार विलेज' के रूप में पहचाना जाएगा।

गाँवों के चयन का आधार

- योजना के तहत लिंगानुपात, शिक्षा, अपराध मुक्त, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन एवं सामाजिक भागीदारी के आधार पर ग्राम पंचायतों का आकलन किया जाएगा।

योजना के मुख्य बिंदु

- हरियाणा की कुल 6,204 ग्राम पंचायतों में से 1120 गाँवों (18 प्रतिशत ग्राम पंचायतों) को स्टार विलेज का दर्जा दिया गया है।
- 6-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले तीन गाँव पलवल ज़िले के है, पाँच स्टार वाले तीन गाँव पलवल एवं रोहतक ज़िले के हैं जबकि 4 स्टार प्राप्त करने वाले 9 गाँव अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार एवं पलवल ज़िले के हैं।
- 407 स्टार रैंकिंग वाले गाँवों के साथ अंबाला ज़िला प्रथम स्थान पर है, जबकि 199 स्टार रैंकिंग वाले गाँवों की रेटिंग के साथ गुरुग्राम नंबर दो तथा 75 स्टार रैंकिंग वाले गाँव रेटिंग के साथ करनाल ज़िला तीसरे स्थान पर है।
- लिंगानुपात में सुधार के बिंदु को तीसरे नंबर और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को दूसरे नंबर पर रखा गया है, इसमें क्रमश: 109 एवं 567 गाँवों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई।

इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018: सूरत को ‘सिटी अवार्ड’
(India Smart City Award 2018: Surat gets 'City Award')

हाल ही में ‘इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड’ 2018 के तहत तीन वर्गों अर्थात् सिटी अवार्ड, नवोन्मेषी विचार पुरस्कार एवं परियोजना पुरस्कार की श्रेणी में 9 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप सूरत को ‘सिटी अवार्ड’ के लिये में चुना गया है।

- 25 जून, 2017 को शहरों, परियोजनाओं एवं नवोन्मेषी विचारों को पुरस्कृत करने तथा नगरों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड को शुरू किया गया।

1) सिटी अवार्ड

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष रूप से शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गत्यात्मकता तथा टिकाऊ समेकित विकास के वर्गों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी प्रदर्शित करने के लिये सूरत को सिटी अवार्ड के लिये चुना गया।

2) नवोन्मेषी विचार पुरस्कार

- नवोन्मेषी विचार पुरस्कार किसी परियोजना/विचार, विशेष रूप से टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके नवोन्मेषी, बॉटम-अप एवं रूपांतरकारी दृष्टिकोण के लिये प्रदान किया जाता है।
- इस वर्ग में संयुक्त विजेता के रूप में भोपाल को समेकित कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के लिये तथा अहमदाबाद को सुरक्षित एवं भरोसेमंद अहमदाबाद (एसएएसए) परियोजना के लिये प्रदान किया गया।

3) परियोजना पुरस्कार

- सात वर्गों में सर्वाधिक नवोन्मेषी एवं सफल परियोजनाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सात वर्गों में अभिशासन, पर्यावरण, सामाजिक पहलू, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, शहरी पर्यावरण, परिवहन एवं गत्यात्मकता व जल एवं स्वच्छता शामिल हैं।

उरुग्वे के बाद कनाडा में भी वैध हुआ मारिजुआना
(Marijuana also validated in Canada after Uruguay)

दिसंबर 2013 में उरुग्वे ने मारिजुआना के उत्पादन, बिक्री और खपत को वैध किया था। इसके बाद अब कनाडा में भी मारिजुआना को वैध बनाने संबंधी विधेयक को पारित किया गया है। 17 अक्तूबर, 2018 से कनाडा में मारिजुआना का इस्तेमाल वैध होगा। इस निर्णय के पीछे सरकार का मकसद संगठित अपराधों में कमी लाते हुए देश के युवाओं को सुरक्षित करना है।

- इस नियमों के तहत कनाडा में वयस्कों को 30 ग्राम तक मारिजुआना खरीदने की अनुमति होगी।
- कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था जिसके तहत कम उम्र के बच्चों को मारिजुआना से दूर रखने और अपराध को कम करने का लक्ष्य तय किया गया था। इस अभियान के अगले कदम के रूप में विधेयक सी-45 (इसे कैनाबिस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है) को प्रस्तुत किया गया।
- कैनाबिस एक्ट के तहत देश के सभी प्रांतों को मारिजुआना के व्यापार को नियमित बनाकर लाइसेंस देने संबंधी अपनी व्यवस्था कायम करने की अनुमति होगी।

भारत में भी शशि थरूर द्वारा मारिजुआना को कानूनी रूप से वैध बनाने संबंधी सुझाव पेश किया गया है। इससे पहले योग शिक्षक रामदेव भी इस तरह की मांग कर चुके हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-22-06-2018